अमेरिका की रार

बौद्धिक संपदा नियमन को लेकर अमेरिका भारत समेत अनेक देशों पर लंबे अरसे से दबाव बनाता आ रहा है. पिछले हफ्ते अमेरिकी वाणिज्य प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारत का नाम उस सूची में बरकरार रखा है, जिसमें शामिल देशों पर उसका आरोप है कि उनकी लापरवाही से अमेरिका के बौद्धिक संपदा अधिकारों को नुकसान हो रहा है. इस सूची में अन्य देश हैं- अलजीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, कुवैत, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन और वेनेजुएला. अमेरिका का कहना है कि भारतीय बाजार में उपलब्ध 20 फीसदी दवाएं नकल कर बनायी जा रही हैं. दवाओं के पेटेंट के कथित उल्लंघन के मामले में उसने चीन और भारत को विशेष रूप से दोषी ठहराया है. भारत ने पिछले साल 19.2 अरब डॉलर मूल्य की दवाओं का निर्यात किया था. इस संबंध में भारत को उस अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत आयात शुल्कों पर छूट है, जिसके तहत विकसित देश विकासशील देशों को सहयोग करते हैं. लेकिन, अमेरिका ने दवाओं समेत अनेक आयातित वस्तुओं पर शुल्क नहीं लगाने की नीति में बदलाव के बारे में भारत को सूचित कर दिया है. ऐसा होने पर अमेरिका को होनेवाले भारतीय निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ सकता है. हालांकि, अमेरिका ने माना है कि भारत ने बौद्धिक संपदा को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाया है, पर उसका आग्रह नियमन को और भी कठोर बनाने का है. निश्चित रूप से यह रुख दबाव बनाने के इरादे से अपनाया गया है. भारत ने वैश्विक नियमों के अनुरूप नियमन करने के साथ यह प्रयास भी किया है कि दवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध हों. विभिन्न विकासशील देशों के सार्वजनिक स्वास्थ्य को इससे बहुत मदद मिली है, क्योंकि गरीब और कम आमदनी के लोग भी दवाएं, खासकर जेनेरिक दवाएं, खरीद पा रहे हैं. दुनियाभर में आपदा पीड़ित लोगों को चिकित्सकीय सेवाएं मुहैया करानेवाली स्वयंसेवी संस्था 'मेडिसिन सांस फ्रंटियर्स' का कहना है कि अमेरिका अपने ताकतवर दवा उद्योग के इशारे पर भारत पर बेमानी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. भारत ने अमेरिकी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि यह सस्ती जेनेरिक दवाओं और तेजी से बढ़ते दवा निर्माण उद्योग के खिलाफ उठाया गया कदम है. इन दवाओं की वैश्विक मांग का 20 फीसदी से अधिक हिस्सा भारत आपूर्ति करता है. अमेरिका में ही भारत के दवा निर्यात का लगभग 30 फीसदी भाग जाता है. हमारा 55 फीसदी निर्यात तो उन देशों में होता है, जहां संबंधित नियमन बहुत मजबूत हैं. ऐसे में सिर्फ अमेरिका को ही भारतीय दवाओं से परेशानी क्यों है? यदि अपने देश के भीतर दवा बाजार को देखें, तो 75 फीसदी से ज्यादा बिक्री जेनेरिक दवाओं की ही होती है. नकली दवाओं की रोकथाम तथा अंतरराष्ट्रीय नियमन के मुताबिक, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा पर अधिक ध्यान देने के साथ नियमन की आड़ में अमेरिका के वाणिज्यिक दबाव का सामना करने की चुनौती सरकार के सामने है.

भारत का 55 फीसदी निर्यात तो उन देशों में होता है, जहां संबंधित नियमन बहुत मजबूत हैं. ऐसे में सिर्फ अमेरिका को ही भारतीय दवाओं से परेशानी क्यों है?

पार्टियां और उसकी सदस्यता

आकार पटेल
कार्यकारी निदेशक,
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया
delhi@prabhatkhabar.in

जब आप भाजपा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाते हैं, तो आपको वहां एक संदेश मिलता है, जिसमें कहा गया है कि 'विश्व के सबसे बड़े दल की वेबसाइट पर आपका स्वागत है.' भाजपा के 10 करोड़ सदस्य हैं. तकरीबरन 10 वयस्क भारतीय में से एक भाजपा का सदस्य है. यह एक चौंका देनेवाला आंकड़ा है. वर्ष 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 16 करोड़ मत मिले थे और उनमें अधिकांश हिस्सा भाजपा का था. इसका अर्थ यह हुआ कि इस पार्टी के लगभग उतने ही सदस्य हैं, जितने इसके मतदाता हैं. इसके आकार का मूल्यांकन करने के लिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) पर एक नजर डालते हैं. चीन एकदलीय शासन प्रणाली का राष्ट्र है. इस पार्टी के नौ करोड़ से अधिक सदस्य हैं, लेकिन इस पार्टी की सदस्यता लेना इतना आसान नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार, सेना, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के सभी शीर्ष पद इस पार्टी के सदस्यों के पास होते हैं.

वर्ष 1921 में सीपीसी के केवल 57 सदस्य थे. वर्ष 2014 में 2.2 करोड़ चीनी लोगों ने सीपीसी की सदस्यता के लिए आवेदन किया था और उनमें से केवल 20 लाख लोगों को सदस्यता मिली. आवेदन करने से सदस्य बनने तक एक वर्ष का समय लगता है. आवेदन में एक पत्र शामिल करना जरूरी होता है, जो यह कहता है कि व्यक्ति सीपीसी पर विश्वास क्यों करता है. इससे तय होता है कि सदस्य के तौर पर उसकी भर्ती होगी या नहीं. उसके बाद आवेदक को एक अनिवार्य परीक्षा पास करनी होती है. परीक्षा में सफल होने के बाद व्यक्ति की स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद उस व्यक्ति को दो ऐसे वर्तमान सदस्यों को तैयार करना होता है, जो उसकी सिफारिश करें. इन सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उस व्यक्ति को परीविक्षा यानी प्रोबेशन पर स्वीकार कर लिया जाता है. जबकि भाजपा इस तरह से अपने सदस्यों को प्रतिबंधित नहीं करती है, लेकिन यह निःशुल्क नहीं है. भाजपा का सदस्यता शुल्क पांच रुपया है और उसके बाद कम से कम 100 रुपये का 'स्वैच्छिक' योगदान देना होता है. इस प्रकार इस पार्टी में शामिल होने के लिए प्रत्येक सदस्य को 105 रुपये या उससे अधिक का योगदान देना होता है. यदि वास्तव में सदस्य बनने की उनकी यही परिभाषा है, तो इस पार्टी ने अकेले सदस्यों से ही 1,000 करोड़ रुपये एकत्रित किये हैं. यह उल्लेखनीय है. इसके ठीक नीचे फार्म में आजीवन सहयोग निधि के तौर पर पार्टी कोष में योगदान के लिए कहा जाता है, जो न्यूनतम 1,000 रुपया है.

पाठकों को यह जानने में रुचि होगी कि भाजपा के संविधान में सभी सदस्यों के लिए यह शपथ लेना अनिवार्य है, जिसमें यह पंक्ति शामिल है, 'मैं पंथनिरपेक्ष राज्य और वैसा राष्ट्र जो पंथ आधारित नहीं है, की अवधारणा में विश्वास रखता हूं.' जो लोग इस दल को इसकी विचारधारा के माध्यम से जानते हैं, उनके लिए दिलचस्प यह है कि भाजपा का संविधान इस पंक्ति से शुरू होता है कि यह 'विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान और समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के इसके सिद्धांतों के प्रति पूरी आस्था और निष्ठा रखेगा.'

चूंकि भाजपा का नेतृत्व एक ऐसा नेता कर रहा है, जो मध्य वर्ग के बीच बहुत लोकप्रिय है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी सदस्यता और स्वयंसेवकों की संख्या का विस्तार होता रहेगा.

अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने मिस्ड कॉल के जरिये लोगों को इसकी तरफ आकर्षित करने का कार्यक्रम शुरू किया. भाजपा विभिन्न शहरों में होर्डिंग्स पर इस फोन नंबर को प्रचारित करती है. इस नंबर पर कॉल करनेवाले व्यक्ति को एक संदेश भेजा जाता है और यह निश्चित करने के लिए कॉल किया जाता है कि वे पैसों का योगदान दे सकते हैं या स्वैच्छिक सेवा कर सकते हैं. एक कंप्यूटर रिकॉर्ड रखा जाता है कि संदेश या कॉल पर प्रत्येक व्यक्ति ने कैसी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने क्या योगदान दिया, अपना समय या पैसा. इस तंत्र के जरिये, पार्टी यह देख सकती है कि समय के साथ किस व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है और वे अपने प्रयासों पर केंद्रित हो सकते हैं. चूंकि भाजपा का नेतृत्व एक ऐसा नेता कर रहा है, जो मध्य वर्ग के बीच बहुत लोकप्रिय है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी सदस्यता और स्वयंसेवकों की संख्या का विस्तार होता रहेगा.

इसके अतिरिक्त यह पार्टी विश्व के सबसे बड़े गैर-सरकारी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ का भरोसा कर सकती है. पूरे भारत में 55,000 से अधिक संघ की शाखाएं हैं. इसके 6,000 पूर्णकालिक प्रचारक हैं, जो वर्तमान में चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं. लोगों को कैसे संगठित करना है, इसके लिए वे वर्षों से प्रशिक्षित किये गये हैं. आरएसएस की विचारधारा और उसके लक्ष्य से भले ही कोई असहमत हो सकता है, लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि उसने जो सेना तैयार की है, वह सक्षम और प्रतिबद्ध है. कुल मिलाकर देखा जाये, तो भाजपा के पास लोगों, नेटवर्क और पैसे के संदर्भ में विश्व की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक मशीन है.

निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का एक लक्ष्य अपने संगठन के पुनर्निर्माण का होगा, ताकि वह भाजपा की बराबरी कर सके. राहुल गांधी पिछले 15 वर्षों से इस दल में हैं, बावजूद इसके अभी तक ऐसा नहीं हुआ है. भारत में अपने पहले 15 वर्षों के दौरान महात्मा गांधी ने चंपारण, खेड़ा, खिलाफत, असहयोग और दांडी नमक आंदोलन का नेतृत्व किया. इस कांग्रेस में हम समान स्तर की जमीनी गतिविधि नहीं पाते हैं. समाज को एकजुट करने के लिए पूर्व में जिस तरह के दृष्टिकोण के साथ यह पार्टी आगे बढ़ी थी, वैसा आज हमें देखने को नहीं मिलता है, या कम से कम मुझे ऐसा नहीं दिखता है. अपने विकास के कारण भी कुछ मायनों में जमीनी स्तर से इसने अपने जुड़ाव को खो दिया है. सेवा दल नाम से कांग्रेस का भी एक स्वयंसेवी संगठन है, जिसकी स्थापना आरएसएस से एक वर्ष पहले हुई थी. यह वह संगठन है जिसने स्वतंत्रतापूर्व के सभी आंदोलनों में कांग्रेस को संसाधन और जन समर्थन मुहैया कराया था. लेकिन स्वतंत्रता के बाद के दशकों में यह क्षीण होता गया, जबकि इस दौरान आरएसएस का लगातार विकास हुआ है.

सदस्यता, खास तौर से शुल्क आधारित सदस्यता, किसी दल की लोकप्रियता का सही सूचक है. कांगेस को अपनी गतिविधियों और भारत के लिए अपनी दृष्टि के आधार पर युवा भारतीयों को अपनी सदस्यता लेने के लिए प्रेरित करने की महती चुनौती है.

बोधि वृक्ष

गुणधर्म

दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं- जड़ हो या चेतन हो, हर वस्तु की अपनी अपनी विशेषता है, अपना गुणधर्म है. उसी में उसकी विशेषता, उसी में उसका जीवन है. किसी वस्तु को अचेतन हम इसलिए कहते हैं कि उसमें स्वतंत्र मन नहीं है. पत्थर की अपनी विशेषता है. बालू में भी अपनी विशेषता है, गुणधर्म है. इस दृष्टिकोण से चेतन में अचेतना में पार्थक्य बहुत कम है. जिसमें मन नहीं है उसे अचेतन कहते हैं और जिसमें मन है उसे चेतन कहते हैं, किंतु पेड़ और पौधों में भी मन है. जानते हो, जिसको हम स्थूल पदार्थ कहते हैं, उसमें भी मन है, विकसित रूप में नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है. मन वहां भी है, किंतु वहां मन को जड़ पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं है. अर्थात जड़ में भी मन और आत्मा है, किंतु उसकी जो सामवायिक संरचना है, उसको मन चला नहीं सकता है. इसलिए एक स्वतंत्र जीवात्मा का अस्तित्व उसके लिए मानना संभव नहीं होता है. पेड़ पौधों में विशेषता क्या है? उनका मन शरीर को चलाता है, किंतु वह मन विवेक के द्वारा परिचालित नहीं होता है. यही पार्थक्य है. समूची दुनिया में जितने मनुष्य हैं, एक वर्ग में आ जाते हैं. इसी कारण मैं कहता हूं कि मानव समाज एक सत्ता है, वह एक और अविभाज्य है. इंसानियत को जो टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, वे धार्मिक नहीं हैं. ऑक्सीजन का अपना धर्म है, नाइट्रोजन का अपना धर्म है, वायु का अपना धर्म है, तथाकथित जड़वस्तु का अपना धर्म है, किंतु जड़ाधार पर मन का नियंत्रण नहीं रहने की वजह से मन की इच्छा अथवा अभीप्सा से जड़ संरचना का कोई संपर्क नहीं रहता है. किंतु पेड़-पौधे, और जीव तथा मनुष्य में ऐसा होता है, क्योंकि कहीं प्रत्यक्ष रूपेण, कहीं अप्रत्यक्ष रूपेण, कहीं कम, कहीं अधिक जड़ संरचना पर मन का प्रभाव होता है. वह मन से परिचालित है और इसकी वजह से उसका धर्म, मुख्यतः उसके मन का धर्म है. मन का धर्म है आनंद की प्राप्ति. अपने कल्याण के लिए, अपनी तरक्की के लिए मन जो कुछ भी करना चाहता है, दूसरों के लिए भी वैसा करना चाहे, तो उसको कहते हैं मानवता.

श्रीश्री आनंदमूर्ति

तेल के बाजार बिगाड़ते कारक

संजय बारू
वरिष्ठ पत्रकार
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक
sanjayabaru@gmail.com

आपूर्ति के पाले में वेनेजुएला से लेकर ईरान तक और मांग के पाले में फ्रांस से लेकिर भारत तक तेल के बाजार में एक बार फिर सियासतदानों और भूराजनीतिक रणनीतिकारों का दखल हावी है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक स्तर पर 'उचित व्यापारिक व्यवहारों' की वकालत करते हुए वेनेजुएला तथा ईरान से तेल के निर्यात पर एकतरफा रोक लगाने जैसे अत्यंत अनुचित व्यापारिक व्यवहार का सहारा लिया है. ट्रंप के इस कदम से न केवल अमेरिका के अमित्र तेल निर्यातकों को, बल्कि उसके भारत जैसे मित्र देशों को भी चोट पहुंचेगी. भारत के कुल ऊर्जा उपभोग में जहां तेल का हिस्सा घटता तथा गैस एवं नवीकरणीयों का बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह भी एक तथ्य है कि पिछले दो दशकों के दौरान भारत के तेल उपभोग में आयातों का हिस्सा तेजी से बढ़कर अब 80 प्रतिशत से भी ऊपर पहुंच चुका है. यही नहीं, इसके और भी अधिक बढ़ते हुए जल्दी ही 90 प्रतिशत से भी अधिक हो जाने का अनुमान भी किया जाता है.

ऊर्जा के वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में संभावित भूराजनीतिक जोखिमें तेल के बाजारों को एक बार पुनः अव्यवस्थित कर दे सकती हैं. इस सामान्य-से दिखते अवलोकन की अहमियत पर जोर दिये बगैर सत्तामूलक सियासत के उस कारक को नहीं समझा जा सकता, जो तेल के बाजारों के साथ-साथ खासकर विश्व की निर्धन अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावनाएं भी सतत बाधित किये दे रहा है. विडंबना यह है कि आर्थिक विश्लेषकों की एक बड़ी तादाद अपने विश्लेषणों में इन जोखिमों को शामिल ही नहीं करती.

भारत कच्चे तेल की अपनी आवश्यकताओं के दो-तिहाई से भी ज्यादा की पूर्ति मुख्यतः इराक, सऊदी अरब एवं ईरान जैसे पश्चिम एशियाई देशों से करता है. पिछले तीन वर्षों में वेनेजुएला से हमारा तेल आयात घटा है, जबकि इसी दौरान ईरान से इसमें बढ़ोतरी हुई है. अमेरिका से भी हमारे यहां इस आपूर्ति का तीन प्रतिशत तेल आता है. ईरान से हमारे तेल आयात के अपने अलग आर्थिक एवं भूराजनीतिक आयाम हैं. आर्थिक आयाम उसके तेल की कीमत है, क्योंकि ईरानी तेल हमारे लिए सस्ता पड़ता है और हाल में तो ईरान से आयातित तेल का यह मूल्य वस्तुओं की अदला-बदली की व्यवस्थाओं द्वारा भी चुकाया गया है. इस आयात का भूराजनीतिक पहलू ईरान द्वारा भारत को अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया तक पहुंच की पेशकश है. हाल में भारत ने पश्चिम एशिया के शिया देशों (इराक एवं ईरान) के साथ ही सुन्नी देशों (सऊदी अरब और यूएई) के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिशें की हैं.

अमेरिका द्वारा ईरान पर आतंक के निर्यात का आरोप पाकिस्तान के साथ अस्पष्ट अमेरिकी नीति के आलोक में खोखला ही लगता है. प्रत्येक देश के अपने विशिष्ट आर्थिक तथा भूराजनीतिक हित होते हैं, जो उसके नीति संबंधी विकल्पों की दिशा तय करते हैं. इसलिए भारत के सामने इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं कि वह अमेरिका तथा ईरान दोनों ही के साथ सामंजस्य बिठाये. उसे अपनी भंगिमाओं से एक ओर तो राष्ट्रपति ट्रंप को प्रसन्न रखना पड़ेगा, जबकि दूसरी ओर उसे ईरान को भी अच्छे रिश्तों का आश्वासन देते रहना होगा. जहां भारत सरकार को तेल की भूराजनीति से निपटना है, वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को तेल की घरेलू सियासत से भी दो-चार होना है. सोनिया कांग्रेस एवं वाम मोर्चे ने सरकार से यह मांग की है कि वह अमेरिका की नीति का अनुसरण न करते हुए ईरान पर उसके द्वारा लगाये प्रतिबंधों को खारिज कर दे. कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वह इस मुद्दे पर एक कमजोर स्थिति में है. भारत को तेल के निर्यातकों में ईरान वर्ष 2013 के सातवें पायदान से उठकर 2018 में तीसरे स्थान पर पहुंच गया.

यह एक सच्चाई है कि यूपीए सरकार के दौरान भी अमेरिकी दबाव के चलते भारत सरकार को समय-समय पर ईरान से तेल के आयात में कमी करनी पड़ती थी. इसलिए कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा मोदी सरकार के लिए इस मामले में दी गयी चेतावनी का कोई अर्थ नहीं है. तथ्य यह है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने ईरान से कच्चे तेल के आयात में 36.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए ईरान को सऊदी अरब तथा इराक के बाद भारत को कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना डाला है.

अलबत्ता, वाम मोर्चा अवश्य ही ईरानी तेल आयात पर अपनी नीति के मुतल्लिक ज्यादा एकरूप रहा है, पर वह उसकी अमेरिका-विरोधी नीति के साथ ही उसके द्वारा अपने मुस्लिम मतदाताओं का ख्याल रखने का प्रतिफल है. यूपीए सरकार के दौरान वाम दल जब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अमेरिका और ईरान के साथ उनकी नीतियों को लेकर नसीहतें देते, तो वे न केवल उन्हें यह याद दिलाना न भूलते कि उन्हें भारत के राष्ट्रीय हितों की पूरी जानकारी है, बल्कि 'विदेश नीति के सांप्रदायीकरण' की उनकी कोशिशों की आलोचना भी किया करते. दरअसल, तेल के बाजारों के लिए राजनीति एवं भूराजनीति की रपटीली राहों से होकर गुजरने के सिवाय कोई अन्य चारा भी तो नहीं है.

(अनुवाद : विजय नंदन)

भारत के सामने इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं कि वह अमेरिका तथा ईरान दोनों ही के साथ सामंजस्य बिठाये. उसे अपनी भंगिमाओं से एक ओर तो राष्ट्रपति ट्रंप को प्रसन्न रखना पड़ेगा, जबकि दूसरी ओर उसे ईरान को भी अच्छे रिश्तों का आश्वासन देते रहना होगा.

आपके पत्र

अमेरिका कौन होता है भारत के लिए नियम तय करने वाला

अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाया गया प्रतिबंध दो मई से लागू हो जायेगा. इस प्रतिबंध से भारत समेत आठ देशों को छह माह की छूट भी समाप्त हो रही है. अब सभी देशों पर अमेरिका का दबाव है कि ईरान से तेल लेना बंद करें, सवाल यह है कि क्या कोई देश दूसरे के स्वार्थ के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल सकता है? विश्व के सभी देश राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं तो फिर अमेरिका कौन होता भारत का नियम तय करने वाला की भारत किससे व्यापार करेगा और किससे नहीं. यदि भारत इस प्रतिबंध का पालन करता है, तो हमे आर्थिक रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा. एक अनुमान है कि पेट्रोल का दाम 10 रुपये तक बढ़ सकता है और महंगाई दर 0.24 बढ़ सकती है. अमेरिका की सदियों पुरानी परंपरा है कि ओ अपने हित के लिए दूसरों को धमकाता है और इस्तेमाल करता है.

आशीष कुमार, बिरनी, गिरीडीह

जनता को है जनता दल यूनाइटेड के घोषणापत्र का इंतजार

17 वें लोकसभा चुनाव का चौथा चरण 29 अप्रैल को संपन्न हो गया. अब तक 377 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है. ये कुल सीटों का 68 फीसदी है. बिहार में 19 सीटों पर भी अब तक चुनाव हो चुका है. बिहार को ही देखें, तो करीब करीब आधा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव का महा कार्य संपन्न हो गया है. देश की तमाम छोटी-बड़ी पार्टियों ने अपना-अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, मगर आश्चर्य की बात है की जनता दल यूनाइटेड ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है. इसका कोई संतोष जनक जवाब पार्टी पदाधिकारियों से नहीं मिल पा रहा है. सीट बंटवारे के हिसाब से भाजपा और जेडीयू 17-17 सीटों पर और लोकजनशक्ति पार्टी छह सीटों पर चुनाव लड़ रही है. जेडीयू का घोषणापत्र जारी नहीं होने का क्या मतलब लगाया जाए ?

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी,जमशेदपुर

इस बार के लोकसभा चुनाव में कम हो रहा है शोर शराबा

देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है. लगभग हर राज्यों में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है. सारी पार्टियां प्रचार प्रसार में मग्न हैं और कार्यकर्ता जी जान लगा कर प्रचार में व्यस्त हैं. हर बार की तरह इस बार भी चुनावी बिगुल फूंका गया, लेकिन बड़े ही शांत तरीके से. अन्य लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव में बहुत फर्क देखने को मिला है. चुनाव आयोग ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए इस लोकसभा को शांत तरीके से कराने का निर्णायक कदम उठाया है. पहले हर जगह प्रचार गाड़ी नारों के साथ पार्टी का प्रचार करती नजर आती थी, जिससे लोगों को परेशानी होती थी. रैलियां शांतिपूर्ण हो रही हैं. एक और खास बात, इस बार सोशल मीडिया प्रचार प्रसार में बड़ी भूमिका निभा रहा है. कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर प्रचार में लगे हुए हैं.

नीलेश मेहरा

कुछ अलग

चुनावी भाषणों का मौसम

वीना श्रीवास्तव
साहित्यकार
veena.rajshiv@gmail.com

नेताओं की तकदीर आजमानेवाला मौसम चल रहा है. जब आम-लीची का मौसम आता है, तो कोयल मस्ती में कूकती है और हम सब उसकी मीठी बोली पर फिदा रहते हैं. मगर इस चुनावी मौसम में कौवे कांव-कांव करते हैं. गधों के साथ गीदड़ भी हुंआ-हुंआ करते हैं, उल्लुओं का डेरा जमा रहता है. बस ऊपर वाले का करम है कि लोग जी रहे हैं, वर्ना ये नेता तो अब तक हमारा लहू चूस चुके होते. चाहे एक जनवरी हो या हिंदु कैलेंडर से चैत का महीना, हम भारतीय तो सब मना डालते हैं. नया साल ही क्यों, हम तो ईद, बुद्ध पूर्णिमा, नानक जयंती, क्रिसमस, दीपावली और होली सब बड़े जोश से मनाते हैं. हम हिंदुस्तानी जो ठहरे. अब आप सुधीजन इसका मतलब धर्म वाला हिंदू से मत लगा लेना. मेरा मतलब है कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं, वे हिंदुस्तानी हैं. हम आपस में भाईचारा पर विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारी नेता बिरादरी 'असली वाला चारा' तो गटक जाती है, लेकिन 'मानवता वाले चारे' को धरोहर के रूप में म्यूजियम में रखती है, ताकि हम बस देखकर ही सुकून कर लें.

बच्चे भी देखकर कहें कि ये गुण कभी हमारे देश के खेवनहारों के चरित्र में मजबूती से पाये जाते थे. वह जमाना और था, जब कोई और गुण हो न हो, लेकिन भाईचारा जरूर होता था. पहले मन से मन और भावनाओं का जुड़ाव ऐसा होता था कि मनमुटाव के बावजूद टोपी और तिलक गलबहियां डाले रहते थे. मगर अब गलबहियों के बीच खेवनहार कीकर की बाड़ क्या, बबूल लगाने में जुटे हैं. अब कोई कोशिश भी नहीं करता कि कीकर की जगह सौहार्दरूपी केसर की पौध लगाये, जिससे आपसी स्नेह की खुशबू पूरे देश में फैले. अब तो फिजा में कांटों की चुभन का आभास हो रहा है.

इसी बीच फिर आ गया चुनावी भाषणों का मौसम. नेताओं के मुख-मंडल पर इतनी सुहानी मुस्कान देखकर हैरत होती है कि तपती धूप, मूसलाधार बारिश, हाड़-मांस जमानेवाली सर्दी में भी हमारे नेता चुनावी मौसम में चेहरे पर शिकन तक नहीं लाते. इसी मुख-मंडल को देखकर लोग कहते हैं कि मजबूरी है, वर्मा कौन इनका चेहरा देखना चाहेगा. देख लो तो दिनभर लगता है भूख हड़ताल पर बैठे हैं. बस अपनी लार ही गटकते रहते हैं. रिश्तों की बयार भी बहने लगती है, मानो पछुआ चलने लगी है. सामने कोई भी आये, सभी पिता तुल्य होते हैं और महिलाएं, माता-बहनें होती हैं. उसके बाद पिता जी लतिया दिये जाते हैं और कुछ मां-बहनों की सिसकियां दफन हो जाती हैं.

चुनावी मौसम के बाद पवन देवता भी नेताओं के साथ पांच सालों के लिए विश्राम पर चले जाते हैं. उसके बाद कोई कितनी कोशिश करे, ऑफिसों, मंत्रालयों के चक्कर में पसीना बहाता रहे, पर मजाल क्या कि उसे सुखाने की कोई जुगत भी भिड़ायी जाये. तो मित्रों! आप अपने जीवन में प्रकृति द्वारा प्रदत्त मौसमों का ही आनंद लीजिये और चुनावी मौसम से आप आगामी मौसमों को किस तरह बदल सकते हैं, इस पर अच्छी तरह से सोच-विचारकर ही बिल्कुल सही का चुनाव करिये.

देश दुनिया से

भारत को जानकारी देने से अमेरिका ने किया इनकार

अमेरिकी सरकार ने बीते फरवरी में हुए भारत-पाक तनाव के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा अमेरिका निर्मित एफ-16 फाइटर जेट के उपयोग में लाये जाने के बारे में भारत को कोई सूचना देने से इनकार कर दिया है. बीते रविवार को ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि भारत ने हमसे इस बारे में जानकारी मांगी थी कि 27 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान ने एफ-16 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था. अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यह अमेरिका और पाकिस्तान के बीच का मामला है, इसलिए यह जानकारी वह भारत को नहीं दे सकता. अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत इस बात को अच्छी तरह समझता भी है, क्योंकि अगर कोई तीसरा देश सी130 या सी17 एयरक्राफ्टों के बारे में कोई जानकारी मांगता है, तब भी हमारा जवाब ना में होगा, क्योंकि यह भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों का मामला है. गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना ने मार्च में पेंटागन से यह शिकायत की थी कि पाकिस्तान ने बीते 27 फरवरी को भारत के खिलाफ एफ-16 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके एंड-यूजर समझौते का उल्लंघन किया था. वहीं पाकिस्तान हमेशा ही भारत के इस आरोप को खारिज करता रहा है.

DAWN

कार्टून कोना

साभार : बीबीसी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है